भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2151

(04.03.2020 को उत्तर के लिए)

प्रशासनिक सुधार आयोग

2151. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी :
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण :
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर :
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सुधारों, नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में ई-क्रांति के तहत कार्यान्वित मिशन मोड परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) सरकार ने अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों जैसेकि लाभार्थियों के खाते में सीधे सब्सिडी अंतरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), अंतर और अंतरा सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत ई-ऑफिस परियोजना, लोगों को महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रानिक रूप में निर्बाध तरीके से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान आदि के माध्यम से देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है ।

(ख) ई-क्रांति के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाओं की पहचान की गई है तथा आंध्र प्रदेश में इन्हें एकल प्लेटफार्म अथवा बहुविध ई-गवर्नेंस पहल के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। पासपोर्ट, आयकर, 21 सेवाओं के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए 21), ई-न्यायालय आदि का

2.....जारी/

कार्यान्वयन पूरा हो गया है । अनेक ई-गवर्नेंस पहल जैसे कि स्वास्थ्य में ई-अस्पताल, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस), आयुष्मान भारत, शिक्षा में शाला दर्पण, एसडब्ल्यूएवाईएएम (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइन्ड्स - मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत शैक्षिक पोर्टल), कृषि में एम-किसान - कृषि और सहकारिता विभाग की पहल, पीएम - किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) आदि के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि इत्यादि जैसे अन्य एमएमपी कार्यान्वित किए गए हैं ।

(ग) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नैतिकता को बढ़ावा देने और जनसाधारण से संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए अपनी चौथी रिपोर्ट "शासन में नैतिकता" में 134 सिफारिशें कीं, जिनमें से 79 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की गईं और उन्हें कार्यान्वयन हेतु संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया ।

****